आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 23.05.2025

समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- भारत सरकार की ओर से गठित संयुक्त संसदीय समिति का दो दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पूरा, समिति ने सभी राज्यों से छह महीने के भीतर ''एक देश, एक चुनाव'' पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
- केंद्र ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी आवास आवंटन का 4 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर ऑनलाइन नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध कराई। मतदाता, पंचायत निर्वाचक नामावली में अपने नाम की कर सकेंगे जांच।

संयुक्त संसदीय समिति उत्तराखंड भ्रमण

भारत सरकार की ओर से गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों से छह महीने के भीतर ''एक देश, एक चुनाव'' पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि यह मुद्दा देशहित से जुड़ा है और सभी राज्यों से इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ–हानि पर अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर समिति की दो दिवसीय बैठक कल देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें उत्तराखंड और महाराष्ट्र से फीडबैक लिया गया। पीपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में यह क्रम टूटा। वर्ष 1994 से इसे दोबारा शुरू करने की कोशिशें हुईं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

उन्होंने बताया कि समिति पर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और किसी जल्दबाजी के बजाय ठोस कार्य पर ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि यदि देशभर में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा, जो जीडीपी का लगभग एक दशमलव छह प्रतिशत होगा। चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों के आवागमन से उद्योगों पर पड़ने वाले असर का भी उन्होंने उल्लेख किया। समिति ने सुझाव दिया है कि अप्रैल–मई का समय एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में कल 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए दो प्रचार वाहनों को रवाना भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिवहन आरक्षी का कार्य सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। यात्री सेवाओं, सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण और प्रदूषण नियंत्रण में इनकी अहम भूमिका होती है।

सीएम धामी ने कर्मचारियों से आमजन के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखने की अपेक्षा जताई। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की कतई न बर्दाश्त करने की नीति को दोहराते हुए बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रभावी सुनवाई हो रही है।

औचक निरीक्षण

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंजीकरण काउंटर, बैठने, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सतपाल महाराज ने देश–विदेश से पंजीकरण कराने आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान तीर्थयात्रियों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की।

पत्रकारों से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने बताया कि अब तक इक्तीस लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम और हेमकुण्ड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है।

सतपाल महाराज ने यह भी बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें 250 यात्री लिपुलेख मार्ग से रवाना होंगे। इसके लिए भारत की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई है कि लिपुलेख से ही श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकें।

रक्षा अलंकरण समारोह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छह कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल थे।

सतर्कता

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चिड़ियाघर में शेर और अन्य जीवों की मौत के बाद राज्य में भी पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू को लेकर विभाग ने दिशा–निर्देश जारी करने के साथ ही पशु चिकित्सकों को संदेह होने पर रक्त जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विद्यासागर कापड़ी ने बताया कि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं है।

विभाग की ओर से सभी डॉक्टरों को संदेह होने पर सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। मुर्गी फार्म और गौ आश्रय स्थलों पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव और सफाई रखने के लिए कहा गया है।

दिव्यांगजन आरक्षण

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में चार प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत बनाती है।

पंचायत मतदाता सूची

राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के लिए पंचायत निर्वाचक नामावली में अपना नाम ऑनलाइन खोजने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। मतदाता अब पोर्टल secvoter.uk.gov.in पर जाकर ''पंचायत मतदाता खोजें'' विकल्प के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं।

आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह सुविधा 17 जनवरी 2025 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर दी गई है। जिन मतदाताओं के नाम पूर्व में किसी कारणवश छूट गए थे, उनके लिए 1 से 22 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की गई थी।

इसके अलावा, जिन लोगों ने इसके बाद आवेदन दिए हैं, उनके नाम भी जिला स्तर से स्वीकृति के बाद पोर्टल पर दिखाई देंगे।

सचिव ने बताया कि अब भी जो पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ना या संशोधित करना चाहते हैं, वे अपने निकटतम विकास खंड या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।

निर्देश

शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कलस्टर विद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभागीय अधिकारियों को 30 जून तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डीपीआर तैयार कर शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के तहत चल रही शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

डॉ. रावत ने अधिकारियों को शीघ्र ही पाँचवीं काउंसिलिंग आयोजित कर दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बीआरपी–सीआरपी की भर्ती में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा।
इसके साथ ही, उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।

कोविड

देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद, प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र व एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की ओर से कोविड रोकथाम के लिए राज्य को निगरानी बढ़ाने के दिशानिर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा है। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कोविड प्रबंधन और रोकथाम के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकिसाधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के दिशा–निर्देश दिए गए। प्रदेश में अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन कोविड संक्रमण रोकने के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज की जांच में कोविड संक्रमण की पुष्टि होती है तो संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोविड जांच, संक्रमित मरीजों की संख्या, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की जानकारी अनिवार्य रूप से आईडीएसपी पोर्टल पर देनी होगी।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...
आज के समाचार पत्रों ने अलग–अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है।
पाक को भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, यह मेरा संकल्प और दुनिया की कोई ताकत इसे डिगा नहीं सकती। प्रधानमंत्री के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– पाकिस्तान को पानी, पाई–पाई के लिये मोहताज कर देंगे।
प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाएंगे सहकारिता मेले, दैनिक जागरण की ख़बर है। समाचार पत्र सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के हवाले से लिखता है– इन मेलों का आयोजन आगामी दस दिसंबर तक होगा, जिनमें सहकारिता गोष्ठी व सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री ने किसी भी सरकारी दस्तावेजों को बनाने से पहले सख्ती से सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जैव विविधता संरक्षण के लिये जनसहभागिता पर जोर दिया है। अमर उजाला समाचार पत्र के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पाया गया कि प्रदेश में खेती को लेकर उदासीनता बढ़ रही है।